हमारे कुछ सहयोगियों की सफलता की यथार्थ के धरातल से दास्तान

ट्रेडक्राफ्ट एक्सचेंज, यूके के साथ भारत में टिकाऊ टैक्सटाइल और टिकाऊ विकास

यह परियोजना राजस्थान में पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही है और पानी एवं ऊर्जा की फिजूलखर्ची रोकते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाते हुए टैक्सटाइल उत्पादन किया जाता है।

वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर के साथ गोदावरी बेसिन, भारत में अधिक पानी और प्रदूषण वाली फसलों का प्रभाव कम करना

इस परियोजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब समुदायों की आजीविका सुनिश्चित की जाए और उन्हें पारिस्थितिकी एवं सेवाओं का समर्थन दिया जाए।

जीईआरईएस के साथ हिमालय की ग्रामीण आबादी को सर्दियों में आजीविका में मदद देना

इस परियोजना के माध्यम से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में लद्दाख में सर्दियों के लिए कम खर्च से सब्जी उत्पादन जारी रखने के लिए ग्रीन हाउसों का निर्माण किया जाता है और इससे 50,000 से अधिक गरीबों की आमदनी एवं पोषण में सहारा दिया गया है।

अनुदान तक पहुंच

यूरोपीय आयोग ऑन लाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है और उसके माध्यम से अनुदान लेना सम्भव है। नीचे दी गयी वेबसाइट नियमित ताजा जानकारी देती है और सभी विवरण उपलब्ध कराती है।

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

सभी प्रस्तावों के उम्मीदवारों को एक समय सीमा के भीतर काम के प्रस्ताव देने को कहा जाता है और उनके उद्देश्य पूछे जाते हैं। सभी आवेदनों की जांच और मूल्यांकन प्रस्तावों की घोषणा के समय निर्धारित पैमानों के आधार पर किया जाता है और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है।

नागरिक समाज की पहल के लिए अनुदान के अवसरों की जानकारी नीचे दिए गए वेबसाइट पते पर उपलब्ध है।

http:// ec.europa.eu/europeaid/who/partner/civil-society/programmes_en.htm

यूरोपीय संघ

भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल
65 गोल्फ लिंक्स, 110003 नयी दिल्ली
फोनः +91–11–24629237, 24629238
फैक्सः +91–11–24629206
वेबसाइटः www.delind.ec.europa.eu

भारत में स्थायी विकास के लिए यूरोपीय संघ का सहयोग

यूरोपीय संघ

भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल

ईयू की मजबूत प्रतिबद्धता

ईयू की अपनी सभी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग में भी पर्यावरण के तमाम पहलुओं का समाधान करने की दीर्घकालिक वचनबद्धता है।

विकास के संबंध में 2005 की यूरोपीय आम सहमति में सामुदायिक कार्यों के विशिष्ट क्षेत्रों और साझा सरोकार के मुद्दों के लिए पर्यावरण के महत्व को रेखांकित किया गया। बाहरी स्तर पर देखें तो यह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों यानी मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स (एमडीजी 7 पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना) के अनुरूप है और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के उद्देश्यों में शामिल है।

भारत में ईयू का समग्र उद्देश्य स्थायी विकास की दिशा में भारत के प्रयासों को समर्थन देना और जलवायु परिवर्तन समेत पर्यावरण के विश्वव्यापी मुद्दों के बारे में आपसी समझबूझ विकसित करना है। ईयू–भारत साझेदारी में पर्यावरण को संवाद का सामरिक क्षेत्र माना गया है और संयुक्त कार्य योजना में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग के आधार तय किए गए हैं। ईयू–भारत पर्यावरण फोरम तथा क्लीन डवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जैसी पहल शुरू होने से दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिली है।

किस प्रकार के कार्यों के लिए अनुदान

इस समय ईयू विभिन्न सहायक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थायी विकास के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सहयोग कर रही है। इनमें शामिल हैं:

- **एक्शन प्लान सपोर्टेड फैसिलिटी (एपीएसएफ) पर्यावरण** कार्यक्रम के तहत पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों– जल, अवशिष्ट, रसायनों, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में तकनीकी सहायता, सलाह और विशेषज्ञता उपलब्ध करायी जा रही है। (www.apsfenvironment.in)
- **ऊर्जा समेत पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम (ईएनआरटीपी)** के तहत पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नागरिक समाज को समर्थन दिया जा रहा है। (www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm)
- **स्विच एशिया** कार्यक्रम में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन एवं उपभोग पर ध्यान दिया जा रहा है। (www.switch-asia.eu)
- **यूरोपियन बिजनेस एंड टैक्नोलॉजी सेंटर** के माध्यम से भारत और यूरोप में बायो टैक्नोलॉजी, ऊर्जा, पर्यावरण, एवं परिवहन क्षेत्रों के लिए स्वच्छ टैक्नोलॉजी के हस्तांतरण संबंधी व्यवसाय के नए अवसर पैदा करने के लिए व्यवसाय, विज्ञान एवं शोध समुदाय को सहायता दी जाती है। (www.ebtc.eu)
- **राज्य साझेदारी** कार्यक्रम के तहत राजस्थान में जल क्षेत्र में सुधार एवं छत्तीसगढ़ में वन आधारित आजीविका के लिए राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण के बारे में समर्थन दिया जा रहा है।
- **ईयू रिसर्च फ्रेमवर्क प्रोग्राम** के माध्यम से भारतीय और यूरोपीय शोध केंद्रों, विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी केंद्रो के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। (www.ec.europa.eu/research/fa7)
- **यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नवीकरण योग्य ऊर्जा एवं ऊर्जा कुशलता के क्षेत्रों के जरिये कम करने की परियोजनाओं को निवेश समर्थन देने के लिए एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एग्ज़िम बैंक) को ऋण उपलब्ध कराता है। (www.eib.org)
- **मानवीय सहायता परियोजनाओं (ईसीएचओ)** के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संबंधी त्रासदियां रोकने के लिए सहायता दी जाती है। (www.ec.europa.eu/echo)

कुल मिलाकर, ईयू ने भारत में सन् 2000 से पर्यावरण संरक्षण एवं स्थायी विकास के लिए करीब 34 करोड़ यूरो से तकरीबन 100 परियोजनाओं को सहारा दिया है।

हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र
(कुल अनुदान देने की पेशकश प्रतिशत में)